चीनी खरीद में मुश्किल

चीनी मिलों को लेवी कोटे से मुक्ति देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में गरीब उपभोक्ताओं को खुले बाजार से खरीदी चीनी सुलभ कराने की केंद्र सरकार की योजना में दिक्कतें आने लगी हैं। पीडीएस में वितरण के लिए खुले बाजार से चीनी खरीदने में पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर समेत पर्वतीय राज्यों ने समस्याएं आने की बात कही है।

छोटे राज्यों को पीडीएस की चीनी खरीद में मुश्किल

पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों ने केंद्र से एक साल तक चीनी सुलभ कराने का अनुरोध किया

प्रेट्र • नई दिल्ली

चीनी मिलों को लेवी कोटे से मुक्ति देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में गरीब उपभोक्ताओं को खुले बाजार से खरीदी चीनी सुलभ कराने की केंद्र सरकार की योजना में दिक्कतें आने लगी हैं। पीडीएस में वितरण के लिए खुले बाजार से चीनी खरीदने में पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर समेत पर्वतीय राज्यों ने समस्याएं आने की बात कही है। हालांकि आंध्र प्रदेश सहित कुछ बड़े राज्यों ने चीनी खरीद के लिए टेंडर जारी करके पहल कर दी है।

खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और लक्षद्वीप ने कहा है कि उनके पास खुले बाजार से चीनी खरीद के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि पीडीएस के तहत वितरण के लिए एक वर्ष तक एफसीआई चीनी प्रदान करे। तब तक राज्य पीडीएस के तहत चीनी वितरित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित कर लेगी।

मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ने सुझाव दिया है कि खुले बाजार से चीनी की खरीद भारतीय खाद्य निगम करे और राज्यों को 13.50 रुपये प्रति किलो की दर पर सुलभ कराए।

पहाड़ी राज्यों ने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा तय की गई 18.50 रुपये प्रति किलो सब्सिडी पर्याप्त नहीं है। पहाड़ी राज्यों में परिवहन खर्च के कारण खुदरा व्यापार में चीनी 45 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है।

दूसरी ओर पीडीएस योजना के तहत वितरण के लिए खरीद के मकसद से दिल्ली व आंध्र प्रदेश ने टेंडर जारी किए हैं। दिल्ली ने जून, जुलाई व अगस्त के लिए 700-2000 टन चीनी खरीद के लिए टेंडर जारी किए है।

आंध्र प्रदेश ने जून की सप्लाई के लिए 11000 टन चीनी का टेंडर जारी किया है। बता दें कि पिछले माह केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त कर दिया था। चीनी मिलें सरकार को 10 फीसदी चीनी सस्ते दाम पर देने के लिए बाध्य नहीं होंगी। राज्यों को पीडीएस में वितरण के लिए चीनी खुले बाजार से खरीदनी होगी। चीनी खरीद पर आने वाले 18.50 रुपए प्रति किलो सब्सिडी केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रदान करेगी। राज्य सरकार को पीडीएस योजना के तहत 13.50 रुपये प्रति किलो के आधार पर चीनी वितरित करनी होती है।

Business Bhaskar

21/5/13